

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	अग्रहायण 15, सोमवार, शाके 1943-दिसम्बर 06, 2021 Agrahayana 15, Monday, Saka 1943- December 06, 2021	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

आदेश

जयपुर, सितम्बर 29, 2021

संख्या प.8(ग)( ) (PSKS) अभियान-2021/नियम/डीएलबी/21/70110 :- इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.8(ग)( ) (PSKS) अभियान-2021/नियम/डीएलबी/21/ 69171 दिनांक 28.09.2021 को अतिक्रमित करते हुए एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 69-ए एवं इसके अन्तर्गत विरचित नियम Rajasthan Municipalities (Surrender of Non-Agricultural Land and Grant of Freehold Lease) Rules, 2015 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्ता शक्तियां का प्रयोग करते हुये फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

(i) दिनांक 02.10.1959 से पूर्व से धारित शहर की चार दीवारी क्षेत्र की सम्पत्तियां- परम्परागत रूप से विकसित पुरानी आबादी/सघन आबादी क्षेत्रों हेतु:-

(क) आवासीय/मिश्रित पट्टा-आवेदक मूल आवंटी अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी होने पर - रुपये 501/- मात्र प्रति पट्टा।

(ख) व्यावसायिक/संस्थानिक/होटल प्रयोजनार्थ पट्टा- 10/- रुपये प्रति वर्गमी.। (न्यूनतम रुपये 5000/-)

(ग) आवेदक मूल आवंटी से भिन्न पश्चातवर्ती क्रेता होने पर:- 10/- रुपये प्रति वर्गमीटर। (न्यूनतम रुपये 5,000/-)

(ii) दिनांक 02.10.1959 से पूर्व शहर की चार दीवारी के बाहर का क्षेत्र-

(क) आवासीय/संस्थानिक/मिश्रित पट्टा आवेदक मूल आवंटी अथवा उसके विधिक उत्तराधिकारी होने पर - 10/- रुपये प्रति वर्गमीटर। (न्यूनतम रुपये 5,000/-)

(ख) आवासीय/संस्थानिक/मिश्रित पट्टा- आवेदक मूल आवंटी से भिन्न पश्चातवर्ती क्रेता होने पर 20/- रुपये प्रति वर्गमीटर। (न्यूनतम रुपये 10,000/-)

(ग) व्यावसायिक/होटल प्रयोजनार्थ पट्टा- 20/- रुपये प्रति वर्गमीटर (न्यूनतम रुपये 10,000/-)

(iii) (दिनांक 02.10.1959 के पश्चात् से दिनांक 01.01.1992 तक धारित सम्पत्तियां:- परम्परागत रूप से विकसित पुरानी आबादी/सघन आबादी क्षेत्रों हेतु -(न्यूनतम रुपये 10,000/-)

• आवासीय/संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 20/- रुपये प्रतिवर्गमीटर।

• मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 25/- रुपये प्रतिवर्गमीटर।

• व्यावसायिक/होटल आदि प्रयोजनार्थ शुल्क 50/- रुपये प्रतिवर्गमीटर।

(iv) गैर-कृषिक खातेदारी भूमि (जिस पर निर्माण हो चुका है), ग्राम पंचायत की आबादी भूमि, ग्रामीण क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम 1971, 1992 एवं 2007 के तहत जारी संपरिवर्तन आदेशों से संबंधित भूमि एवं

नगरीय क्षेत्र भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 के तहत जारी गैर-कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण आदेश, कस्टोडियन-(न्यूनतम रुपये 20,000/-)

- आवासीय/संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 50/- रुपये प्रति वर्गमीटर।
- मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 75/- रुपये प्रति वर्गमीटर।
- व्यावसायिक/होटल प्रयोजनार्थ शुल्क 100/- रुपये प्रति वर्गमीटर।

(v) पूर्व राजा-महाराजाओं/उनके परिवार के सदस्यों/पूर्व जागीरदारों द्वारा स्वयं के स्वामित्व की भूमि का **भूखण्डों के रूप में दिनांक 02.10.1959 के पश्चात् व दिनांक 01.01.1992 से पूर्व विक्रय किया गया है।**  
(न्यूनतम रुपये 30,000/-)

- आवासीय/संस्थानिक प्रयोजनार्थ शुल्क 50/- रुपये प्रति वर्गमीटर।
- मिश्रित प्रयोजनार्थ शुल्क 100/- रुपये प्रति वर्गमीटर।
- व्यावसायिक/होटल आदि प्रयोजनार्थ शुल्क 150/- रुपये प्रति वर्गमीटर।

- नोट:-** (i) उपरोक्त सभीश्रेणियों में आवासीय/संस्थानिक/मिश्रित की नियमन राशि अधिकतम 5 लाख रुपये एवं व्यावसायिक/होटल प्रयोजनार्थ की नियमन राशि अधिकतम 10 लाख रुपये होगी।
- (ii) मिश्रित से तात्पर्य नीचे दुकान-ऊपर मकान।
- (iii) फ्री-होल्ड पट्टे पर कोई लीज राशि वसूलनीय नहीं होगी। 99 वर्षाीय लीज डीड/पट्टा/रूपान्तरण आदेश सरेण्डर कर पट्टा प्राप्त करता है तो बकाया लीज राशि एवं 10 वर्षाीय एक मुश्त लीज राशि वसूल की जाकर ही पट्टा जारी किया जायेगा। भूमि रूपान्तरण आदेशों में लीज राशि की गणना रूपान्तरण शुल्क की 4 गुना राशि को आवासीय दर मानते हुए 2.5 प्रतिशत एवं व्यावसायिक में 5 प्रतिशत की दर से राशि देय होगी।
- (iv) आवेदित प्रकरण में मौके पर उपलब्ध भूखण्ड/भवन का क्षेत्रफल आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व दस्तावेजों (प्रूफ ऑफ राइट्स) से अधिक होने की स्थिति में स्वामित्व दस्तावेजों से अधिक क्षेत्रफल पर आवासीय आरक्षित दर का 10 प्रतिशत या डी.एल.सी. का 10 प्रतिशत जो भी कम हो, राशि वसूल कर सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा जारी किया जायेगा। यदि अतिरिक्त भूमि किसी संरक्षित स्थल का हिस्सा है तो उसका आवंटन नहीं किया जावेगा।
- (v) राजकीय कार्यालय हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- (vi) नजूल सम्पत्तियों की आवंटन दरें पृथक से राज्य सरकार द्वारा तय की जावेगी। उपरोक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

दीपक नन्दी,  
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।